Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

28 - 29 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत ने वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2025 में, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MoCAF&PD) के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग वैश्विक भुखमरी को दूर करने, चावल की आपूर्ति को मज़बूत बनाने और भारत की मानवीय पहलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

• इस समझौते पर भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आशुतोष अग्निहोत्री, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए WFP के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानमाली, WFP के उप-कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउ, भारत में WFP के कंट्री डायरेक्टर बिशो परजुली और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (DFPD) के सचिव संजीव चोपड़ा जैसे वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। उनकी भागीदारी ने "वसुधैव कुटुम्बकम" के दर्शन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसका अर्थ है कि विश्व एक परिवार है।

• आशय पत्र में अगले पाँच वर्षों में भारत द्वारा 2,00,000 मीट्रिक टन (MT) तक फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति का अनुमान लगाया गया है। इस फोर्टिफाइड चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मध्याह्न भोजन योजना और पोषण अभियान जैसे पोषण संबंधी सरकारी कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख कम करने के प्रयासों को बल मिलेगा।

• यह आशय पत्र फरवरी 2025 में रोम, इटली में विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान हुई चर्चाओं पर आधारित है। यह भारत के खाद्यान्न की कमी वाले देश से मानवीय खाद्य सहायता के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में परिवर्तन को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने खाद्य वितरण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, विशेष रूप से संकट की स्थितियों के दौरान, बढ़ती भूमिका निभाई है।

Key Points:-

(i) विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ चल रहे सहयोग में अन्नपूर्ति योजना के अंतर्गत अनाज ATM की स्थापना, समुदायों के लिए खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु स्वचालित टेलर मशीनें (ATM), स्मार्ट भंडारण प्रणालियाँ और मोबाइल भंडारण इकाइयों (रोस्पांस) की शुरुआत जैसी पहल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जन पोषण केंद्रों (JPKs) को समुदाय-आधारित पोषण जागरूकता और पौष्टिक आहार के प्रसार केंद्रों के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ii) ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ, भारत को मज़बूत खाद्य सुरक्षा मॉडल और कूटनीतिक प्रभाव के लिए मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 और मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) के समर्थन से, भारत पोषण और खाद्य प्रणालियों में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ मिलकर काम कर रहा है।

2. वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक बारगी बदलाव की शुरुआत की।

अगस्त 2025 में, वित्त मंत्रालय (MoF) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकमुश्त, एकतरफ़ा स्विच सुविधा की घोषणा की, जिससे वे एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में स्थानांतरित हो सकेंगे। यह विकल्प 30 सितंबर, 2025 तक उपलब्ध रहेगा।

• नई घोषित स्विच सुविधा, एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत नामांकित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में स्थानांतरित होने की अनुमति देती है। यह कदम सेवानिवृत्ति योजना में अधिक लचीलापन प्रदान करने और एनपीएस ढांचे के माध्यम से दीर्घकालिक निधि निर्माण को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

• दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महीने पहले तक इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

• यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को अपने पेंशन विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करने का अंतिम अवसर मिले।

Key Points:-

(i) एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि एक बार स्विच करने का विकल्प चुनने पर, कर्मचारी UPS के तहत अपने सभी अधिकार, जिनमें किसी भी सुनिश्चित भुगतान लाभ शामिल हैं, हमेशा के लिए खो देंगे। यह निर्णय अपरिवर्तनीय है, और कर्मचारी एनपीएस चुनने के बाद यूपीएस में वापस नहीं जा सकते, जो इस सुविधा की एकमुश्त और बाध्यकारी प्रकृति को दर्शाता है।

(ii) स्विच करने पर, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के निकास एवं निकासी विनियम, 2015 के तहत निकास एवं निकासी प्रावधान स्वतः लागू हो जाएँगे। इससे यह विनियमित होगा कि कर्मचारी एनपीएस ढांचे के तहत अपनी सेवानिवृत्ति निधि और वार्षिकी तक कैसे पहुँच सकते हैं।

(iii) भारत सरकार (GOI) ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिफ़ॉल्ट निवेश पैटर्न के अनुसार गणना करके 4% का अंतर अंशदान, कर्मचारी के NPS कोष में निकासी के समय जमा किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि NPS में स्थानांतरण के बाद भी सरकारी सहायता जारी रहेगी।

3. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा ने मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और कई स्वास्थ्य कल्याण पहलों की शुरुआत की।

मध्य प्रदेश के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश (जे. पी.) नड्डा ने दो सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और कई स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत की। ये कार्यक्रम जबलपुर और श्योपुर-सिंगरौली में हुए, जिससे चिकित्सा अवसंरचना में सुधार और समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के केंद्र के प्रयासों को बल मिला।

• केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा के नेतृत्व में श्योपुर और सिंगरौली में दो नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। ये कॉलेज राज्य के वंचित और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और सेवाओं की पहुँच बढ़ाएँगे। यह चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में आयोजित उद्घाटन समारोह में, नड्डा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा प्रभारी) और विधायक हेमंत खंडेलवाल के साथ समारोह की अध्यक्षता की। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर चार अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये संस्थागत विस्तार चिकित्सा शिक्षा को भौगोलिक रूप से सुलभ और किफ़ायती बनाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

• जे. पी. नड्डा ने कई स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रमों की भी घोषणा की: वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के लिए 8 लाख "वय वंदना" PVC कार्ड का वितरण, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में नागरिकों का मार्गदर्शन करने के लिए "आयुष्मान सखी" स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ, "स्वस्थ लिवर" पहल के तहत 1 करोड़ लिवर स्वास्थ्य जाँच के लक्ष्य तक पहुँचने वाले "स्वास्थ्य जागरूकता मिशन" को मान्यता, और अग्रिम पंक्ति की आशा कार्यकर्ताओं को मंत्रालय से जोड़ने के लिए एक संचार मंच "आशा संवाद" का शुभारंभ। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पहलों को नई सूचनात्मक सामग्री और मातृ एवं शिशु सुरक्षा (MCP) कार्ड के साथ बढ़ाया गया।

Key Points:-

(i) अपने संबोधन में, केंद्रीय मंत्री नड्डा ने स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया, जो निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, वृद्धावस्था और प्रोत्साहन उपायों पर केंद्रित था। उन्होंने संस्थागत प्रसव दर के 89% तक पहुँचने और मातृ मृत्यु दर (MMR) में प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 93 हो जाने पर प्रकाश डाला, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा परिणामों में सुधार पर ज़ोर दिया गया।

(ii) इन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्तरित हस्तक्षेप - भारत की प्रमुख स्वास्थ्य योजना, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम भी माना जाता है - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास को दर्शाता है।

(iii) ये सभी प्रगतियाँ भारत के विकसित होते स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य की पुष्टि करती हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढाँचे का मज़बूती से विस्तार करके और नागरिक-केंद्रित डिजिटल एवं भौतिक कल्याण पहलों की शुरुआत करके, सरकार सभी के लिए सुलभ, समान और प्रभावी प्राथमिक एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को

मज़बूत कर रही है।

4. OpenAI ने IIT मद्रास के साथ मिलकर "इंडिया-फर्स्ट" लर्निंग एक्सेलरेटर लॉन्च किया और 5 लाख मुफ्त चैटजीपीटी लाइसेंस वितरित किए।

अगस्त 2025 में, OpenAI ने भारत में अपने लर्निंग एक्सेलरेटर का अनावरण किया - अपनी पहली ऐसी पहल - जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) को ₹4.5 करोड़ (USD 500,000) का अनुसंधान अनुदान, और देश भर में छात्रों और शिक्षकों को 500,000 चैटजीपीटी लाइसेंस का मुफ्त वितरण शामिल है, जिसका उद्देश्य AI-संचालित शिक्षा को बढ़ावा देना है।

• IIT मद्रास के साथ साझेदारी में, OpenAI ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने और नवीन शिक्षण विधियों को बढ़ावा देने के तरीके पर दीर्घकालिक शैक्षिक अनुसंधान को समर्थन देने के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4.5 करोड़) देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह सहयोग संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान से प्राप्त अंतर्दृष्टि के अनुरूप है, और सभी निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने और भविष्य के AI अनुप्रयोग डिज़ाइन में शामिल करने का लक्ष्य है।

• लर्निंग एक्सेलरेटर के तहत, OpenAI अगले छह महीनों में पाँच लाख चैटजीपीटी लाइसेंस निःशुल्क वितरित करेगा। ये लाइसेंस शिक्षा मंत्रालय (MoE), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और एसोसिएशन फॉर रीइन्वेंटिंग स्कूल एजुकेशन (ARISE) के साथ साझेदारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएँगे, जिसमें सरकारी स्कूल और AICTE-विनियमित तकनीकी संस्थान शामिल होंगे।

• इस पहल के तहत, छात्रों और शिक्षकों के बीच ज़िम्मेदार AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए जाएँगे। लर्निंग एक्सेलरेटर का उद्देश्य कक्षा की कार्यप्रणाली, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम अपनाने में AI को एकीकृत करना है, खासकर CBSE और IIT प्रवेश की तैयारी के लिए। इस कार्यक्रम की योजना बुनियादी स्मार्टफ़ोन पर चलने वाले और 11 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाले AI टूल्स को सक्षम करके शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा देने की भी है।

Key Points:-

(i) OpenAI ने INSEAD-प्रशिक्षित कार्यकारी और कोर्सेरा के पूर्व प्रबंध निदेशक (भारत एवं एशिया-प्रशांत) राघव गुप्ता को अपना शिक्षा प्रमुख (भारत एवं एशिया-प्रशांत) नियुक्त किया है। वे लर्निंग एक्सेलरेटर का नेतृत्व करेंगे और स्कूलों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में रणनीतिक साझेदारियों, एआई प्रशिक्षण और शैक्षिक उपकरणों तक पहुँच का समन्वय करेंगे।

(ii) OpenAI की शिक्षा उपाध्यक्ष, लीह बेल्स्की के अनुसार, भारत में चैटजीपीटी के 50% से ज़्यादा उपयोगकर्ता 24 वर्ष से कम आयु के हैं और पढ़ाई के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "चैटजीपीटी का अध्ययन मोड" भारतीय पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया गया है और अंततः स्थानीय भाषाओं को भी सपोर्ट करेगा, जिससे OpenAI की वैश्विक शिक्षा रणनीति में भारत की भूमिका एक "प्रकाश स्तंभ" के रूप में रेखांकित होती है।

(iii) यह लर्निंग एक्सेलरेटर भारत के शिक्षा

पारिस्थितिकी तंत्र में OpenAI के अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। यह लॉन्च AI के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है और OpenAI के पहले भारतीय कार्यालय की नई दिल्ली में स्थापना से पहले हुआ है, जहाँ वैश्विक CEO सैम ऑल्टमैन के जल्द ही आने की उम्मीद है।

5. NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 'प्रोजेक्ट आरोहण' शुरू किया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में भारत भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता और समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है।

• इस परियोजना की औपचारिक घोषणा NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने की, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना आरोहण टोल प्लाजा कर्मचारियों और उनके परिवारों को समर्थन देने के लिए प्राधिकरण की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

• उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल युवाओं की शैक्षणिक प्रतिभा को पोषित करने के लिए तैयार की गई है, जिससे वे भारत की दीर्घकालिक वृद्धि और विकास में योगदान दे सकें।

• योजना के अनुसार, प्रोजेक्ट आरोहण कक्षा 11 से लेकर स्नातक अंतिम वर्ष तक के 500 छात्रों को कवर करेगा। प्रत्येक चयनित छात्र को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए ₹12,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य वित्तीय बोझ कम करना और शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना है।

Key Points:-

(i) स्नातक स्तर की शिक्षा के अलावा, यह परियोजना स्नातकोत्तर या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। लगभग 50 मेधावी छात्रों को उन्नत शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष ₹50,000 की राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(ii) पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी, जहाँ छात्रों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड, आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण अपलोड करने होंगे। यह डिजिटल प्रक्रिया सुगमता सुनिश्चित करती है, कागजी कार्रवाई को कम करती है और लाभार्थियों के लिए संपूर्ण चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाती है।

(iii) प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत करके, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कर्मचारी कल्याण, शैक्षिक असमानताओं को कम करने और टोल प्लाजा श्रमिकों के बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

6. PM मोदी ने मारुति सुजुकी की पहली भारत में निर्मित BEV 'e-VITARA' लॉन्च की और गुजरात में

स्थानीयकृत हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन का उद्घाटन किया।

26 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV), ई-विटारा के उत्पादन का शुभारंभ किया। पूरी तरह से भारत में निर्मित इस SUV का 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। साथ ही, घरेलू स्वच्छ ऊर्जा निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन संयंत्र का भी संचालन शुरू हो गया है।

• गुजरात के हंसलपुर प्लांट में, प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) e-VITARA का उद्घाटन किया। यह B-सेगमेंट बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) पूरी तरह से भारत में निर्मित है और यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात के लिए तैयार है।

• इस लॉन्च में तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के बीच एक संयुक्त उद्यम, टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्वदेशी उत्पादन की शुरुआत भी शामिल थी। इसके साथ, अब बैटरी का 80% से अधिक मूल्य घरेलू स्तर पर ही तैयार किया जाएगा, जिससे "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।

Key Points:-

(i) e-VITARA और बैटरी सुविधाओं के साथ, भारत सुजुकी के वैश्विक EV निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। रेल कनेक्टिविटी और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से सुसज्जित हंसलपुर संयंत्र अब वैश्विक बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर BEV उत्पादन का समर्थन करता है।

(ii) सुजुकी मोटर ने अगले 5-6 वर्षों में भारत के ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹70,000 करोड़) का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। हंसलपुर संयंत्र की अनुमानित वार्षिक क्षमता दस लाख यूनिट है, जो e-VITARA के विनिर्माण पैमाने को मज़बूत करेगी।

(iii) यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के सतत परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने और भारत-जापान सहयोग को मज़बूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा था। उन्होंने "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" की थीम पर ज़ोर दिया और स्वच्छ परिवहन और हरित नवाचार में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला।

INTERNATIONAL

1. रूस स्वेर्दलोवस्क और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक श्रम की कमी से निपटने के लिए 2025 तक 1 मिलियन भारतीय श्रमिकों की भर्ती करेगा।

गहराते कार्यबल संकट के बीच, रूस 2025 के अंत तक दस लाख कुशल भारतीय पेशेवरों को लाने की तैयारी कर रहा है। गंभीर श्रम घाटे से प्रेरित यह कदम, विशेष रूप से स्वेर्दलोवस्क जैसे औद्योगिक केंद्रों को लक्षित करता है और इसे पायलट समझौतों और विस्तारित श्रमिक कोटा के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है।

- **आंद्रे बेसेदिन के नेतृत्व में यूराल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 10 लाख तक भारतीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की योजना का खुलासा किया है - मुख्य रूप से स्वेर्दलोवस्क क्षेत्र में, जो भारी मशीनरी, धातु विज्ञान और यूरालमाश तथा UralVagonZavod जैसे टैंक निर्माण कारखानों के लिए जाना जाता है - जो यूक्रेन में संघर्ष और घटती जन्म दर के कारण श्रमिकों की कमी से जूझ रहे हैं।**

- **रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने पुष्टि की कि रोज़गार के अवसरों की तलाश में ज़्यादा भारतीय कामगारों के आने से कॉन्सुलर की माँग में वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की रूसी कंपनियाँ रूसी क़ानूनों और कोटा के दायरे में भारतीयों की सक्रिय रूप से भर्ती कर रही हैं।**

Key Points:-

(i) इन घोषणाओं के बावजूद, रूस के श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 10 लाख भारतीय कामगारों की भर्ती की किसी भी योजना से इनकार किया है, और स्पष्ट किया है कि विदेशी श्रम की भर्ती पूर्व निर्धारित कोटा द्वारा नियंत्रित होती है—2025 में सभी विदेशी कामगारों के लिए कुल संख्या लगभग 2,34,900 होगी, जिसमें 71,817 विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित हैं। स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र में, वर्तमान कोटा केवल 4,343 है।

(ii) रूस में श्रमिकों की कमी तेज़ी से बढ़ रही है। श्रम मंत्रालय का अनुमान है कि 2030 तक 31 लाख श्रमिकों की कमी हो जाएगी। इसके जवाब में, संघीय सरकार 2025 के लिए विदेशी श्रमिकों के कोटे में 1.5 गुना वृद्धि पर विचार कर रही है ताकि दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय चुनौतियों के जारी रहने के दौरान तत्काल दबाव को कम किया जा सके।

(iii) आने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए, भारत येकातेरिनबर्ग में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापित कर रहा है, जो वाणिज्य दूतावास सेवाओं, वीज़ा प्रक्रिया और श्रमिक सहायता को सुव्यवस्थित करेगा। इसके अतिरिक्त, संभावित प्रवासियों को रूसी औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा दक्षता और तकनीकी कौशल से लैस करने के लिए भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

BANKING & FINANCE

1. टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य से जुड़ी बीमा और डिजिटल वेलनेस सेवाओं को मजबूत करने के लिए 'हेल्थ SIP प्लान' और 'हेल्थ बडी' ऐप लॉन्च किया है।

अगस्त 2025 में, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड (AIA) के संयुक्त उद्यम, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में दो प्रमुख पेशकशें शुरू कीं—हेल्थ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (हेल्थ SIP) और हेल्थ बडी एप्लीकेशन। इन पहलों का उद्देश्य पूरे भारत में

पॉलिसीधारकों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सहायता को एक साथ लाना है।

• हेल्थ SIP प्लान अपनी तरह का पहला नॉन-पार्टिसिपेटिंग यूनिट-लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जिसे प्रीमियम आवंटन शुल्क हटाकर दीर्घकालिक फंड वैल्यू प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैच्योरिटी बूस्टर भी शामिल है, जो पॉलिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करता है और साथ ही एक स्वास्थ्य सुरक्षा जाल भी बनाता है।

• हेल्थ SIP की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए छठे पॉलिसी वर्ष से कर-मुक्त निकासी की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, यह 30 वर्षों की अधिकतम प्रीमियम लॉक-इन अवधि के साथ गंभीर बीमारियों को कवर करता है, जिससे परिवारों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

Key Points:-

(i) हेल्थ SIP दो अलग-अलग प्रकारों में उपलब्ध है: हेल्थ SIP प्लस, जो आकस्मिक पूर्ण और स्थायी विकलांगता के विरुद्ध अतिरिक्त कवरेज प्रदान करता है, और हेल्थ एसआईपी प्लस प्रो, जो बेहतर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टर्म बूस्टर लाभ के साथ लाइलाज बीमारी को कवर करता है। यह दोहरी संरचना ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार लचीलापन प्रदान करती है।

(ii) बीमा पेशकश के साथ-साथ, टाटा AIA ने हेल्थ बडी ऐप भी लॉन्च किया है, जो एक 24×7 वर्चुअल वेलनेस और स्वास्थ्य साथी सेवा है। यह एप्लिकेशन निवारक स्वास्थ्य जांच, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा सहायता, दंत परामर्श और 24 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञताओं में वर्चुअल सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे यह एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है।

(iii) हेल्थ SIP और हेल्थ बडी के संयुक्त लॉन्च के साथ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य से जुड़े वित्तीय समाधानों में खुद को एक प्रर्वतक के रूप में स्थापित किया है, जो अपने ग्राहकों को सुरक्षा और निरंतर स्वास्थ्य सहायता दोनों प्रदान करने के लिए बीमा और प्रौद्योगिकी को जोड़ता है।

2. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने वित्त वर्ष 2025 में 134 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और भर्ती पर लगी रोक को समाप्त करने का प्रयास किया।

डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹134 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो मज़बूत वृद्धि का संकेत है। बैंक के प्रबंधन ने अब कर्मचारियों और सेवाओं के विस्तार के लिए लंबे समय से चली आ रही भर्ती पर रोक हटाने का प्रस्ताव रखा है।

• वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, IPPB ने ₹134 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक उल्लेखनीय बदलाव है। यह उपलब्धि एक सरकारी भुगतान बैंक के रूप में इसके परिचालन लचीलेपन और दक्षता को रेखांकित करती है।

• IPPB 12 करोड़ ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जिसकी कुल जमा राशि ₹20,000 करोड़ तक पहुँचती है। यह पैमाना, वंचित ग्रामीण और शहरी

बाज़ारों में व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाकर पहुँच बनाने में इसकी सफलता को दर्शाता है।

• बैंक का परिचालन मार्जिन वित्त वर्ष 2023 में लगभग 3.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 12.5% हो गया है, जो बढ़ी हुई राजस्व दक्षता और सख्त लागत प्रबंधन को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) IPPB ने सरकार से 2020 से लागू अपनी भर्ती रोक को हटाने के लिए औपचारिक अनुरोध किया है। बैंक का अनुमान है कि बढ़ती सेवा मांगों को पूरा करने के लिए उसे क्षेत्रीय परिचालन और कॉर्पोरेट भूमिकाओं में लगभग 1,000 कर्मियों की आवश्यकता है।

(iii) भुगतान से आगे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए, IPPB HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, आदित्य बिड़ला कैपिटल फाइनेंस और आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण ऋण पहुँच को और मज़बूत कर रहा है। यह कृषि, स्वर्ण, व्यक्तिगत और किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने वाले विभिन्न छोटे-छोटे डिजिटल ऋण प्रदान कर रहा है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. IRSE अधिकारी एस.सी. जैन को अतिरिक्त प्रभार के साथ रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) का CMD नियुक्त किया गया।

अगस्त 2025 में, रेल मंत्रालय (MoR) ने भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (IRSE) के वरिष्ठ अधिकारी, एस.सी. जैन को रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी। वे 31 अगस्त, 2025 को प्रदीप गौड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद, 1 सितंबर, 2025 को आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे।

• एस.सी. जैन भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (IRSE) के 1988 बैच के हैं और रेलवे परियोजनाओं में 28 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव रखते हैं।

• उनकी विशेषज्ञता बुनियादी ढांचे के विकास, परियोजना निष्पादन और कुशल परियोजना प्रबंधन में फैली हुई है, जो उन्हें RVNL की महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं के लिए उपयुक्त नेता बनाती है।

• वर्तमान में, जैन रेल मंत्रालय में सलाहकार (भूमि एवं सुविधाएँ) के पद पर कार्यरत हैं। अपनी सलाहकार भूमिका में, उन्होंने राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में भूमि प्रबंधन, सुविधाओं के विकास और परिचालन सुधार से संबंधित प्रमुख रेल परियोजनाओं में योगदान दिया है।

Key Points:-

(i) रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL), रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह भारत भर में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें लाइन दोहरीकरण, विद्युतीकरण, मेट्रो परियोजनाएं और प्रमुख निर्माण कार्य शामिल हैं।

(ii) निवर्तमान CMD प्रदीप गौड़, जो 31 अगस्त, 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, से नए CMD एस.सी. जैन के नेतृत्व में RVNL की चल रही परियोजनाओं में निरंतरता सुनिश्चित होगी। जैन के नेतृत्व में, RVNL द्वारा अपनी कार्यान्वयन गति में तेज़ी लाने और भारत के रेलवे बुनियादी ढाँचे के विस्तार में अपनी भूमिका को मज़बूत करने की उम्मीद है।

(iii) यह नियुक्ति रेल मंत्रालय की रणनीति को दर्शाती है, जिसमें प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुभवी IRSE अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और प्रबंधकीय क्षमता को मजबूती मिलती है।

2. मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।

भारतीय भारोत्तोलक सनसनी मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शानदार वापसी की। इस जीत ने न केवल एक साल के अंतराल के बाद उनकी वापसी को चिह्नित किया, बल्कि खेल में नए मानक भी स्थापित किए।

- **नए शुरू किए गए 48 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए, मीराबाई चानू ने कुल 193 किलोग्राम भार उठाया—स्नैच में 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 109 किलोग्राम। उनके प्रदर्शन ने तीनों श्रेणियों: स्नैच, क्लीन एंड जर्क, और कुल भारोत्तोलन में मौजूदा राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए।**

- **यह चैंपियनशिप मीराबाई की 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद पहली उपस्थिति थी, जहाँ वह पदक से चूक गई थीं। अहमदाबाद में पोडियम पर उनकी वापसी उनके खेल के प्रति दृढ़ता और समर्पण का प्रमाण थी।**

Key Points:-

(i) स्वर्ण पदक जीतकर, मीराबाई ने 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया। यह उपलब्धि खेल में उनके निरंतर प्रभुत्व को रेखांकित करती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मंच तैयार करती है।

(ii) मीराबाई की जीत का व्यापक रूप से जश्न मनाया गया और हर तरफ से प्रशंसा मिली। उनके प्रदर्शन ने न केवल भारत को गौरवान्वित किया है, बल्कि दुनिया भर के महत्वाकांक्षी एथलीटों को भी प्रेरित किया है। उनके परिवार और प्रशंसकों का समर्थन उनके शीर्ष पर वापस पहुँचने के सफ़र में एक महत्वपूर्ण प्रेरक रहा है।

(iii) अक्टूबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के साथ, मीराबाई का राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उनकी तैयारियों के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करता है। अहमदाबाद में उनके प्रदर्शन ने उनकी क्षमताओं में आत्मविश्वास जगाया है, और वह इस खेल में उत्कृष्टता की अपनी खोज जारी रखने के लिए तैयार हैं।

SPORTS

1. खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का उद्घाटन डल झील, श्रीनगर में हुआ।

युवा मामले और खेल मंत्रालय (MoYAS), भारत सरकार ने 21 से 23 अगस्त 2025 तक डल झील, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल (KIWSF) 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। जल-आधारित खेलों को बढ़ावा देने और जलीय विषयों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन के तहत 3 दिवसीय मेगा खेल आयोजन की मेजबानी की गई थी।

- **KIWSF 2025 के उद्घाटन संस्करण में भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रतिनिधित्व करने वाले 500 से ज़्यादा एथलीट शामिल हुए। इस महोत्सव में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग की पदक स्पर्धाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 24 पदक दांव पर थे।**

- **इसके साथ ही, खेल और कश्मीरी परंपरा के सम्मिश्रण को उजागर करने के लिए शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस और वाटर स्कीइंग जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।**

- **इस उत्सव की ब्रांडिंग चपलता और विरासत की थीम पर आधारित थी। आधिकारिक शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था, जो गति, ऊर्जा और सटीकता का प्रतीक था। डल झील पर तैरते एक पारंपरिक कश्मीरी शिकारे के इर्द-गिर्द डिज़ाइन किया गया लोगो, एक खेल स्थल के रूप में कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व, दोनों को दर्शाता था।**

Key Points:-

(i) मध्य प्रदेश (MP) उद्घाटन संस्करण का समग्र चैंपियन बनकर उभरा, जिसने 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ओडिशा और केरल क्रमशः दूसरे और तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। मध्य प्रदेश ने कयाकिंग और कैनोइंग स्पर्धाओं में अपना दबदबा कायम रखा, दूसरे दिन सभी चार स्वर्ण पदक जीते और समापन दिवस तक अपना दबदबा बनाए रखा।

(ii) KIWSF 2025 का एक प्रमुख आकर्षण डल झील के 17 वर्षीय स्थानीय शिकारावाला, मोहसिन अली का प्रदर्शन रहा। उन्होंने 1000 मीटर पुरुष कयाकिंग दौड़ में 4 मिनट 12.41 सेकंड का समय लेकर इस महोत्सव का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी जीत ने न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की, बल्कि कश्मीर के जमीनी स्तर के खेल समुदायों से उभरती प्रतिभा को भी उजागर किया।

(iii) भविष्य को देखते हुए, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव को 2026 से एक व्यापक खेलो इंडिया जल खेलों में विस्तारित किया जाएगा।

2. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के राजगीर में हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 ट्रॉफी का अनावरण किया।

हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 ट्रॉफी का अनावरण हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने किया। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर, 2025 तक बिहार के नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। यह राज्य का पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय हॉकी आयोजन है।

- **इस टूर्नामेंट में आठ शीर्ष एशियाई टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें दो पूलों में बाँटा गया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत, पूल ए में जापान, चीन और कज़ाकिस्तान के साथ है। भारत का पहला मैच 29 अगस्त को चीन से होगा और फाइनल 7 सितंबर को होगा।**

- **यह संस्करण नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले 2026 FIH (अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ) पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफायर के रूप में कार्य करता है। विजेता सीधे क्वालीफाई करता है, जबकि अन्य शीर्ष टीमें अगले वर्ष के क्वालीफायर में प्रवेश करती हैं।**

Key Points:-

(i) बिहार खेल विश्वविद्यालय के भीतर स्थित राजगीर हॉकी स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया गया है, जो विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना के प्रति बिहार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और राज्य को वैश्विक आयोजनों के स्थल के रूप में बढ़ावा देता है।

(ii) यह टूर्नामेंट हॉकी इंडिया द्वारा एशियाई हॉकी महासंघ और बिहार राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य हॉकी को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों का प्रदर्शन बढ़ाना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है।

(iii) तैयारियों में भारतीय टीम के लिए प्रशिक्षण शिविर और अन्य प्रतिभागी देशों द्वारा टीमों का चयन शामिल है। इस आयोजन से मीडिया कवरेज, प्रायोजन और प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे एशिया में हॉकी की छवि मज़बूत होगी।

3. भारत विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में 8 पदकों के साथ चमकेगा।

कनाडा के विन्निपेग में 17 से 27 अगस्त तक आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में, भारत ने कुल आठ पदक जीतकर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया: चार स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य। यह उपलब्धि वैश्विक तीरंदाजी क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित करती है।

- **इस चैंपियनशिप में 63 देशों के 570 तीरंदाज़ों ने विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की। भारत के उल्लेखनीय प्रदर्शनों में अंडर-21 महिला कंपाउंड वर्ग में चिकिथा तनिपर्थी का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक शामिल था, जो इस स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक था।**

• इसके अतिरिक्त, शारवरी शेंडे ने अंडर-18 महिला रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता, यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह केवल तीसरी भारतीय महिला बनीं।

• टीम स्पर्धाओं में, भारतीय पुरुष अंडर-18 और अंडर-21 कंपाउंड टीमों ने क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीते। अंडर-18 मिश्रित कंपाउंड टीम ने भारत के पदकों में रजत पदक जोड़ा, जिससे देश में प्रतिभा की गहराई का पता चला।

Key Points:-

(i) पृथिका प्रदीप ने अंडर-18 महिला कंपाउंड व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में रजत पदक जीतकर भारत की सफलता में योगदान दिया। उनके निरंतर प्रदर्शन ने भारत के युवा तीरंदाजी कार्यक्रम की ताकत को उजागर किया।

(ii) चैंपियनशिप ने उभरती प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। पृथिका प्रदीप और शर्वरी शेंडे जैसी एथलीटों ने अपने लचीलेपन और कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे वैश्विक प्रतियोगिताओं में भविष्य की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(iii) कुल मिलाकर, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रदर्शन युवा प्रतिभाओं को पोषित करने के प्रति देश की प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है।

IMPORTANT DAYS

1. आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 सितम्बर को मनाया गया।

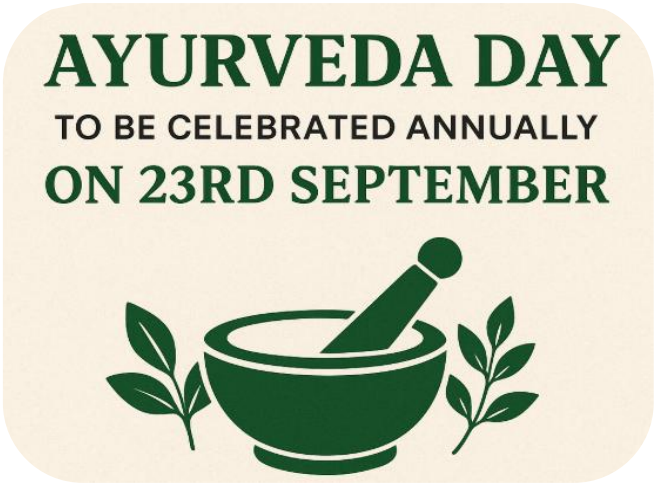

वैश्विक मान्यता और निरंतरता को बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। 23 मार्च 2025 की एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया यह निर्णय, परिवर्तनशील चंद्र कैलेंडर के अनुसार धनतेरस के साथ इस दिन को जोड़ने की पिछली प्रथा में बदलाव का प्रतीक है।

• आयुर्वेद दिवस का पहला दिन 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में दिव्य चिकित्सक भगवान धन्वंतरि की जयंती धनतेरस के दिन मनाया गया।

• इस अवसर का उद्देश्य आयुर्वेद को एक वैज्ञानिक, साक्ष्य-आधारित और समग्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में बढ़ावा देना था, तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण में इसकी भूमिका पर जोर देना था।

• 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की एकरूपता सुनिश्चित करना और बेहतर नियोजन को सुगम बनाना है। धनतेरस के दिन इस दिन को मनाने की पुरानी प्रथा, इसकी बदलती तिथि के कारण, जो चंद्र कैलेंडर के आधार पर हर साल बदलती रहती थी, चुनौतियों का सामना करती

थी। एक निश्चित तिथि अधिक संगठित और व्यापक समारोहों के लिए अवसर प्रदान करती है।

Key Points:-

(i) चुनी गई तिथि शरद विषुव के साथ मेल खाती है, वह दिन जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यह खगोलीय घटना प्रकृति में संतुलन का प्रतीक है, जो आयुर्वेदिक दर्शन के अनुरूप है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पर ज़ोर देता है। इस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाना आयुर्वेद के सार—प्रकृति के साथ संतुलन में रहना—को रेखांकित करता है।

(ii) एक निश्चित तिथि निर्धारित करके, भारत सरकार का उद्देश्य आयुर्वेद की वैश्विक दृश्यता को बढ़ाना और सार्वभौमिक स्तर पर समग्र कल्याण के इसके सिद्धांतों को बढ़ावा देना है।

(iii) आयुष मंत्रालय व्यक्तियों, स्वास्थ्य पेशेवरों, शैक्षणिक निकायों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को नई निर्धारित तिथि को अपनाने और प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

BOOKS & AUTHORS

1. संजय बारू की पुस्तक "सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल: द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया" का आधिकारिक विमोचन हुआ।

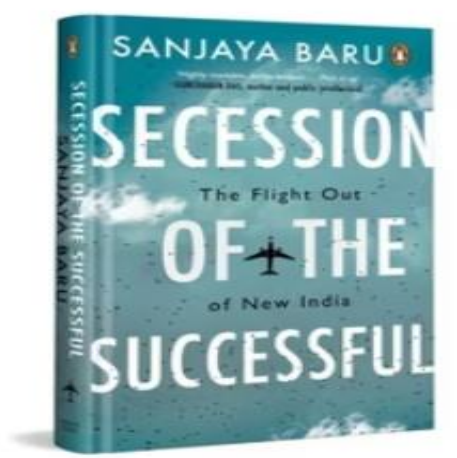

राजनीतिक टिप्पणीकार और नीति विश्लेषक संजय बारू द्वारा लिखित पुस्तक "सफलता का अलगाव: नए भारत की उड़ान" पेंगुइन वाइकिंग इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक भारतीयों द्वारा स्थायी रूप से विदेश में बसने के बढ़ते चलन पर प्रकाश डालती है, और बारू द्वारा "नॉन-रिटर्निंग इंडियंस" कहे जाने वाले लोगों की मानसिकता और प्रेरणाओं पर प्रकाश डालती है।

• पुस्तक में, बारू भारत में प्रवास की एक चौथी लहर की पहचान करते हैं, जो पिछली लहरों से अलग है, और जो आवश्यकता के बजाय धन, शक्ति और विशेषाधिकार से प्रेरित है। यह लहर उन संपन्न भारतीयों के विकल्पों को दर्शाती है जो नए अवसरों, सुरक्षा और वैश्विक संपर्क की तलाश में हैं।

• बारू ने नागरिकता त्याग के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 2022 में 2.25 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी और 2023 में 2.16 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी। कुल मिलाकर, 2011 से 2023 तक, लगभग 1.9 मिलियन भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, जो प्रवासन प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

• लेखक भारतीय प्रवासियों को चार श्रेणियों में बाँटते हैं: कानून से भगोड़े, पहली पीढ़ी के धनी व्यक्ति जो खुद को राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, अनिश्चित शासन से जोखिम कम करने या विविधता लाने की चाह रखने वाले लोग, और विदेश में बेहतर जीवन स्तर की तलाश में रहने वाले लोग। प्रत्येक श्रेणी विशिष्ट प्रेरणाओं और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है।

Key Points:-

(i) बारू का काम इन "गैर-वापस लौटने वाले भारतीयों" को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों की भी पड़ताल करता है, तथा यह जांच करता है कि राजनीतिक अनिश्चितता, शासन

संबंधी चुनौतियां और व्यक्तिगत आकांक्षाएं किस प्रकार भारत को स्थायी रूप से छोड़ने के निर्णय में योगदान करती हैं।

(ii) यह पुस्तक नीतिगत निहितार्थों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और नीति निर्माताओं से इस प्रतिभा और धन के पलायन के परिणामों को समझने का आग्रह करती है। बारू का तर्क है कि अत्यधिक कुशल और संपन्न भारतीयों का पलायन भारत की आर्थिक वृद्धि, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

(iii) अंत में, "सफल लोगों का अलगाव" प्रवासन, शासन और नागरिक सहभागिता पर एक व्यापक बहस को प्रोत्साहित करता है, जो समकालीन भारत में स्थायी प्रवासन को संचालित करने वाले व्यक्तिगत विकल्पों और प्रणालीगत कारकों के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करता है।

Static GK

World Food Programme (WFP)	कार्यकारी निदेशक (ED) : सिंडी मैक्केन	मुख्यालय : रोम, इटली
Ministry of Finance (MoF)	केंद्रीय मंत्री: निर्मला सीतारमण	मुख्यालय: नई दिल्ली
Madhya Pradesh (MP)	मुख्यमंत्री (CM) : डॉ. मोहन यादव	राज्यपाल : मंगूभाई छगनभाई पटेल
OpenAI	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : सैम ऑल्टमैन	मुख्यालय : कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
National Highways Authority of India (NHAI)	अध्यक्ष: संतोष कुमार यादव (IAS)	मुख्यालय: सेक्टर-10, द्वारका, दिल्ली
Russia	राजधानी: मास्को	प्रधान मंत्री: मिखाइल मिशुस्टिन
Gujarat	मुख्यमंत्री: भूपेन्द्र पटेल	राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
India Post Payments Bank Limited (IPPB)	सचिव: विनीत पांडे	मुख्यालय: नई दिल्ली
Ministry of Youth Affairs and Sports (MoYAS)	मनसुख मंडाविया	दिल्ली
Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान